Result Mitra Daily Magazine

खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में बफर स्टॉक का महत्व

- मई 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अनाज के लिए मुद्रास्फीति 8.69%, जबकि दालों के लिए 17.14% थी।
- यह और अधिक हो सकती थी, लेकिन अधिशेष उत्पादन वर्षों के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाए गए बफर स्टॉक ने इन्हें नियंत्रित करके रखा।
- दरअसल 2022-23 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने 34.82 लाख टन गेहूं बाजार में बिक्री के लिए उतरा, ताकि आपूर्ति में कमी न हो, जिसने मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाई।
- 2023-24 में यह आपूर्ति, जो विशेषकर ई-नीलामी के जरिए आटा-मिल मालिकों को उपलब्ध करवाई गई थी, बढ़कर 100.88 लाख टन पहुंच गई।
- इसमें से 6.73 लाख टन गेहूं को आटा में बदलकर 'भारत आटा' ब्रांड के तहत 27.5 रुपए/Kg के हिसाब से बेचा गया।
- FCI की इस नीति ने अनाज एवं गेहूं की मुद्रास्फीति, जो फरवरी में 2023 में क्रमशः 16.73% और 25.37% हो गई थी, को मई 2024 में क्रमशः 8.69% एवं 6.53% तक ला दिया।

बफर स्टॉक का ह्रास –

- पिछले 3 वर्षों में गेहूं का उत्पादन प्रभावित रहा, जिसके कारण 1 July 2021 को FCI के पास जहाँ 603.56 लाख टन गेहूँ का स्टॉक था, वहीं यह 2022 एवं 2023 (1 July) को घटकर क्रमशः 285.10 लाख टन और 301.45 लाख टन रह गया। हालांकि यह मात्रा खुले बाजार में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त था।

Result Mitra

चना दाल का कीमत नियंत्रण –

- वर्ष 2023 से ही दालों की कीमत काफी बढ़ी है और मुद्रास्फीति दोहरे अंक में रही है।
- उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार चना दाल का खुदरा मूल्य वर्तमान में 90 रुपए/Kg है, जबकि 1 वर्ष पूर्व यह 70 रुपए/Kg था।
- इसी दौरान अरहर की कीमत 120 रुपए/Kg से 170 रुपए/Kg, उड़द एवं मूंग की कीमत 110 रुपए/Kg से 120 रुपए/Kg और मसूर दाल की कीमत 100 रुपए/Kg हो गई।
- यह स्थिति और ज्यादा खराब होती है, अगर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) ने 2021-22 और 2022-23 में बम्पर खरीद न की होती और आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए इन्हें खुले बाजार में न बेचा होता।
- NAFED ने 2022 एवं 2023 के दौरान क्रमशः 25.56 लाख टन एवं 23.53 लाख टन दाल का स्टॉक किया, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपए/क्विंटल (2022) और 5335 रुपए/क्विंटल (2023) पर खरीदी गई थी, जबकि उसी दौरान महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की मंडियों में चना 4400 – 4800 प्रति क्विंटल बिक रहा था।
- NAFED का स्टॉक अल नीनो के कारण खराब मौसम एवं खराब फसल के कारण दालों की कीमतों में संभावित वृद्धि को रोकने में सफल रहा।
- NAFED ने जुलाई 2023 से खुले बाजार में ई-नीलामी से 14.06 लाख टन चना बेचा है, जबकि 60 रुपए/किलोग्राम के दर से 16.09 लाख टन चना 'भारत दाल' को, 2.91 लाख टन चना रियासत दरों पर राज्य सरकारों को एवं 0.57 लाख टन चना सशस्त्र बलों को उपलब्ध करवाया है।

बफर नीति का मामला –

- खाद्य कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन के कारण ज्यादा बढ़ गई है।
- बारिश के कम दिन, लंबे समय तक सूखा, कभी-कभार तीव्र वर्ष एवं चरम मौसमी परिस्थितियों ने RBI के लिए भी मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दरों में कटौती करने के विचार को मुश्किल बना दिया है।
- सरकार निर्यात को प्रतिबंधित करने एवं व्यापारियों एवं प्रसंस्करण कर्ताओं पर स्टॉक की सीमा लागू करने के लिए मजबूर है ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे।
- सभी आवश्यक वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाया जाना, इन उलझनों से बचने का तरीका हो सकता है।
- अधिशेष उत्पादन वर्षों के दौरान किसानों से खरीदकर बफर स्टॉक में रखा जाए और फसल विफलताओं के समय कीमतों को कम करने के लिए इसे बेचा जाए तो मुद्रास्फीति नियंत्रण संभव है। वर्तमान में सरकारी एजेंसियों द्वारा MSP के तहत मुख्यतः चावल, गेहूं, चना, अरहर, मसूर, सरसों, मूंगफली आदि को ही खरीदा जाता है, जबकि इसका विस्तार अन्य दालों एवं तिलहनों के साथ-साथ मुख्य सब्जियों के अलावा स्किम्ड मिल्ड पाउडर (SMD) तक किए जाने की गुंजाइश है।

Result Mitra

- खरीदे गए प्याज, आलू एवं टमाटर आदि को होटल, रेस्तरों एवं अन्य संस्थागत खरीददार को पेस्ट, फ्लेक्स एवं प्यूरी के रूप में संग्रहित कर बेचा जा सकता है। जिससे ये कीमत बढ़ाने के लिए अन्य खरीददार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे।
- वर्तमान में SMP की कीमतें 315 – 320 रुपए/किलोग्राम से घटकर 210 रुपए/किलोग्राम हो गई है, जिसने महाराष्ट्र डेयरियों को दूध की कीमत 37-38/लीटर से घटाकर 27-28 रुपए/लीटर करने को मजबूर कर दिया है।
- यह सरकार के पास एक अवसर जैसा है कि क्यों न SMP को अभी जारी भारी मात्रा में खरीदकर बफर स्टॉक बनाया जाए एवं जब दूध की कमी होगी तो बाजार में इसे बेचकर महंगाई को नियंत्रित किया जाए।
- जिस प्रकार RBI का विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने में मददगार होता है, ठीक उसी प्रकार बफर स्टॉक खाद्य-कीमतों की अस्थिरता को रोकने में मददगार होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य –

- बफर स्टॉक की अवधारणा चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान विकसित हुई।
- यह स्टॉक भारत सरकार द्वारा FCI के अधीन रखा जाता है।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति प्रत्येक तिमाही बफर स्टॉक का न्यूनतम मानदंड निर्धारित करती है।
- NAFED, FCI और लघ-कृषक व्यावसायिक संघ दालों की खरीद के लिए अधिकृत हैं।
- स्किम्ड माइल्ड पाउडर में वसा और वसा में घुलने वाले विटामिन के बजाय पानी में घुलने वाले विटामिन पाए जाते हैं।
- स्किम्ड मिल्ड पाउडर में प्रोटीन 26% एवं कार्बोहाइड्रेट 37% होता है लेकिन वास की मात्रा न्यून रहती है।

Result Mitra